जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

epaper.rashtradoot.com

जालोर

Rashtradoot

फोनः- 226422, 226423 फैक्सः- 02973-226424 वर्षः 19 संख्याः 274 प्रभात जालोर, बुधवार 8 जनवरी, 2025 पो. रजि. /RJ/SRO/9640/2022-24 पृष्ठ 6 मूल्य 2.50 रु.

दिल्ली की मु.मंत्री आतिशी सिंह ने आरोप लगाया, तीन महीने में दूसरी बार बेघर किया केन्द्रीय सरकार ने

भाजपा ने प्रत्युत्तर में कहा, आतिशी को बेघर करने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि ग्यारह अक्टूबर को ''शीश महल'' ऑफर हुआ, पर, उन्होंने आज तक उसका कब्जा नहीं लिया है, अतः शीश महल का उनका आवंटन रद्द करना पड़ा था

-श्रीनंद झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 7 जनवरी। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी सिंह के दावे, कि केन्द्र सरकार ने उनका घर छीन लिया है और भाजपा के इसके जोरदार खंडन के बाद कंट्रोलर एण्ड ऑडिटर जनरल (सी.ए.जी.) की एक रिपोर्ट आई है जिसमें केजरीवाल के बंगले की मरम्मत व साज-सज्जा पर हुए भारी खर्च का जिक्र हैं।

ऑडिटर रिपोर्ट जिसे दिल्ली विधानसभा में पेश नहीं किया गया में बताया गया है कि केजरीवाल के बंगले 6, फ्लैग स्टाफ रोड के लिए पर्दे खरीदने पर 96 लाख रुपए, इटालियन मार्बल की खरीद पर 14 लाख रुपए और मार्बल स्टोन पर 66 लाख रु. खर्च किए। शुरुआत में मरम्मत व साज-सज्जा पर 7.91 करोड़ रु. खर्च होने का अनुमान था पर काम खत्म होते-होते यह खर्च बढ़कर 33.66 करोड़ रु. हो गया।

केजरीवाल के शीश महल पर मंगलवार को तब विवाद बढ़ा जब मुख्यमंत्री आतिशी सिंह ने दावा किया कि केन्द्र सरकार ने तीन माह में दूसरी बार उनसे आवास छीन लिया, उन्हें दिया हुआ आवंटन रद्द करके। इस पर भाजपा के अमित मालवीय ने एक्स पर लिखा कि मुख्यमंत्री को कभी भी निकाला नहीं गया। असल में वे कभी भी शीश महल में गई ही नहीं जो उन्हें गत वर्ष 11 अक्टूबर को आवंटित हुआ था।

- इस संबंध में भाजपा ने यह कटाक्ष भी किया कि केजरीवाल ने बहुत तबियत से, अपने मु.मंत्री निवास ''शीश महल'' को 33.66 करोड़ रूपये खर्च करके ठीक-ठाक कराया। अतः आतिशी केजरीवाल के ''शीश महल'' में शिफ्ट करके केजरीवाल की नाखुशी नहीं लेना चाहती थीं, इसलिए शीश महल को उन्होंने अपना निवास कभी नहीं बनाया।
- 33.66 करोड़ रूपये ''रैनोवेशन'' पर खर्च होने की बात सी.ए.जी. ने अपनी रिपोर्ट में भी कही है।
- पर, दिल्ली में विधानसभा चुनाव से दो महीने पहले ही रिपोर्ट आना इस घटनाक्रम में राजनीतिक पुट होने का संदेह जरूर जगाती है। सी.ए.जी. की रिपोर्ट का केजरीवाल के वफादार वोट बैंक पर कितना असर होगा, यह अभी नहीं आंका जा सकता।

भाजपा नेता ने आतिशी पर झूठ बोलने का आरोप लगाया और पब्लिक वर्क्स डिपार्टमैंट के दो पत्र शेयर किए जिनमें स्पष्ट किया गया था आवंटन वापस लिया गया क्योंकि आतिशी कभी इसमें गईं ही नहीं। इसकी बजाय उन्हें दो बड़े बंगले आवंटित किए गए। मालवीय ने कहा, उन्होंने शीश महल में रहना स्वीकार नहीं किया क्योंकि वो केजरीवाल को नाराज़ नहीं करना चाहती थी।''

शीश महल विवाद अगले माह होने वाले विधानसभा चुनाव में आप के लिए शुभ संकेत नहीं है। क्योंकि इससे केजरीवाल की आम आदमी के नेता की छवि खराब हो सकती है।

सी.ए.जी. रिपोर्ट की टाइमिंग महत्वपूर्ण है। यद्यपि यह स्पष्ट नहीं है कि क्या रिपोर्ट के निष्कर्ष आप के जनाधार पर नकारात्मक और दूरगामी प्रभाव डाल सकते है। सी.ए.जी. रिपोर्ट में बताया गया है कि खर की मरम्मत और साजसज्जा में कितने महंगे आइटम प्रयुक्त किए गए। मुख्यमंत्री आवास में 8 शयन कक्ष, तीन मीटिंग रुम, दो ड्राईंग रुम, दो किचन और 12 टॉयलैट है। यहां तक कि टॉवल रैक व सोप होल्डर

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

नाबालिग से अश्लीलता करने वाले को 5 साल की सजा

जयपुर, 7 जनवरी। पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-3 महानगर, द्वितीय, ने 6 साल की पीड़िता के साथ अश्लीलता करने वाले अभियुक्त परमा उर्फ गोलू को पांच साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर पांच हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। पीठासीन अधिकारी नरेन्द्र सिंह मालावत ने अपने आदेश में कहा कि ऐसे अपराधों से समाज की नैतिकता और बालिकाओं की सुरक्षा का खतरा है। इसलिए अभियुक्त के प्रति नरमी का रुख नहीं अपनाया जा सकता।

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक ललिता संजीव महरवाल ने अदालत को बताया कि घटना को लेकर पीड़िता के परिजनों ने 17 नवंबर, 2023 को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में कहा गया कि उसके पास वाले कमरे में किराए पर रहने वाले अभियुक्त ने उसकी छह साल की बेटी को कमरे में बुलाया और अश्लील हरकत की। पीड़िता का रोना सुनकर जब वे कमरे में गए तो अभियुक्त ने पीड़िता के कपडे खोल रखे थे और उससे अश्लीलता कर रहा था।

- पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने 17 नवम्बर, 2023 की घटना पर निर्णय सुनाया।

रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

क्या बिहार में राष्ट्रपति शासन लगेगा?

केन्द्रीय गृह मंत्री द्वारा बिहार दौरा रद्द करने से अटकलों का बाज़ार गर्माया

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 7 जनवरी। तेजस्वी यादव ने बिहार के गवर्नर से मुलाकात की ओर संकेत दिया कि नीतीश कुमार की सरकार 24 घंटे में सत्ता से बाहर हो जाएगी।

उन्होंने राज्यपाल से कहा कि पटना में छात्र उग्र हो रहे हैं। तेजस्वी ने गवर्नर को लिखे अपने पत्र में कहा कि नीतीश हिंसा की साजिश रच रहे हैं।

दिल्ली में भाजपा सूत्रों ने कहा कि तेजस्वी ने पटना में दंगे की चेतावनी दी है, इससे नीतीश को सत्ता से हटाकर भाजपा को सत्ता में आने में मदद मिलेगी।

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी धमकी मिली है कि उन्हें पद से हटा दिया जाएगा। शाह ने दो दिन पहले बिहार दौरा भी स्थगित कर दिया और अब वे बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाने पर विचार कर रहे हैं ताकि अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा को सत्ता में आने में मदद मिल जाएगी।

- समझा जाता है कि मोदी और शाह नीतीश से सख्त नाराज हैं, कारण है, नीतीश और लालू यादव की मुलाकात।
- बताया जाता है कि नीतीश, प्र.मंत्री मोदी से मिलने दिल्ली गए, पर, मोदी ने उन्हें मुलाकात का समय ही नहीं दिया।
- तेजस्वी यादव ने भी राज्यपाल से मुलाकात की और मुलाकात के बाद कहा कि 24 घंटे में नीतीश सरकार चली जाएगी।

नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से बात करने दिल्ली गए थे पर मोदी ने नीतीश को मिलने का समय ही नहीं दिया। भाजपा बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाने का विचार कर रही है। छात्रों ने पटना में चक्का जाम कर रखा

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

जवाब नहीं दिया तो मानेंगे, सरकार एस.आई. भर्ती रद्द करना चाहती है

जयपुर, 7 जनवरी। राजस्थान हाईकोर्ट ने एसआई भर्ती-2021 के मामले में स्पष्ट किया है कि यदि सरकार ने इस मामले में कोई जवाब नहीं दिया तो यह माना जाएगा कि वह एसआईटी की रिपोर्ट, एजी की राय और कैबिनेट सब कमेटी की ओर से भर्ती रद्द करने की सिफारिश पर सहमत है। वहीं, इसे आधार मानते हुए अदालत भी अपना फैसला देगी। अदालत ने राज्य सरकार को कहा है कि वह 9 जनवरी को एसआईटी की 13 अगस्त 2024 की रिपोर्ट, एजी की 14 सितंबर 2024 की विधिक राय व कैबिनेट सब कमेटी की 7 अक्टूबर व 10 अक्टूबर 2024 की बैठकों का विस्तृत रिकार्ड भी पेश करे। जस्टिस समीर जैन ने ये निर्देश कैलाश चन्द्र शर्मा व अन्य के प्रार्थना पत्र पर दिए। अदालत की ओर से मंगलवार को यह आदेश सार्वजनिक करने पर यह जानकारी सामने आई है।

- हाई कोर्ट ने एस. आई. टी. की रिपोर्ट, ए.जी. की विधिक राय तथा कैबिनेट सब कमेटी की बैठकों का विस्तृत रिकॉर्ड भी मांगा।

अदालत ने कहा कि यदि 18 नवंबर 2024 के आदेश में दिए गए निर्देशों के विपरीत जाकर कोई भी कार्रवाई या फील्ड पोस्टिंग दी जाती है, तो इसके जिम्मेदार अफसर व व्यक्तियों के खिलाफ भी निर्णायक कार्रवाई की जाएगी। वहीं, यदि इस संबंध में कोई

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

चीन अरुणाचल प्रदेश में नये आतंकवादी ग्रुप, ''यूनाइटेड टानी आर्मी'' को पनपा रहा

इस ग्रुप का मुख्य ध्येय भारत द्वारा अरुणाचल प्रदेश में ''हाइड्रो इलैक्ट्रिसिटी'' जनरेट करने के लिये प्रस्तावित बड़े-बड़े बाँधों के निर्माण का विरोध करना है

-सुकुमार साह-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 7 जनवरी। भारत के अरुणाचल प्रदेश में चीन एक उग्रवादी समूह ''यूनाईटेड टानी आर्मी'' (यू.टी.ए.) के गठन में सक्रिय भूमिका निभा रहा है। यू.टी.ए. का मुख्य लक्ष्य क्षेत्र में बड़े पैमाने पर हो रहे बांध निर्माण का विरोध करना है और उसमें व्यवधान डालना है। ये बांध परियोजनाए भारत के ''क्लीन एनर्जी'' लक्ष्य तथा क्षेत्रीय विकास के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं क्योंकि इनका उद्देश्य अरुणाचल प्रदेश के हाइड्रो इलैक्ट्रिक क्षमता का पूरा लाभ उठाना है जिससे भारत की ''ऊर्जा सुरक्षा'' बढ़ सकती है।

चीन की विस्तृत रणनीति, जिसका लक्ष्य भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में अस्थिरता फैलाना है, के तहत यू.टी.ए. की स्थापना की गई है। ऐसे उग्रवादी संगठनों को समर्थन व सहायता देकर चीन भारत के लिए आन्तरिक सुरक्षा चुनौतियां पैदा करना चाहता है जिससे नई दिल्ली को अपनी ऊर्जा व संसाधन

- हाल ही में इस आतंकवादी ग्रुप ने एक वक्तव्य जारी कर अरुणाचल में बड़े बाँधों के निर्माण का तो विरोध किया ही, साथ में कई क्षेत्रीय भावात्मक मांगों को साथ में जोड़ दिया। जैसे, चकमा जनजाति के विस्थापितों को बसाने के लिये सरकार की व्यवस्था में कमियां-खामियों को उजागर करना तथा आदिवासी महिलाओं के गैर-आदिवासी पुरुषों से शादी व इस विवाह से उत्पन्न बच्चों को आदिवासी ''स्टेटस'' देने का विवाद आदि।
- चीन जानता है, ऐसे भावात्मक मुद्दे उठाने से इस आतंकवादी संगठन से कुण्ठित युवा जुड़ेगा तथा चीन, भारत के नॉर्थ-ईस्ट क्षेत्र को अस्थिर कर सकेगा और वहाँ अशांति बनी रहेगी।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

न्याय मित्र महिला टॉयलैट्स के हालात पर रिपोर्ट पेश करे

जयपुर, 7 जनवरी। राजस्थान हाईकोर्ट ने कार्यस्थल और सार्वजनिक जगहों पर महिलाओं के लिए टॉयलैट्स की कमी व मौजूदा टॉयलैट्स में आधारभूत सुविधाओं की कमी से जुड़े मामले में केन्द्र व राज्य सरकार से पूछा है कि महिला टॉयलैट्स के मौजूदा हालात क्या हैं और महिला शौचालयों के सुधार के लिए उनकी क्या कार्य योजना है। इसके साथ ही अदालत ने मामले से जुड़े न्याय मित्रों को कहा है कि वे भी सर्वे कर महिला शौचालयों के हालातों पर अपनी रिपोर्ट पेश करें। सीजे एमएम श्रीवास्तव व जस्टिस उमाशंकर व्यास की खंडपीठ ने यह आदेश मंगलवार को प्रदेश में महिला शौचालयों में आधारभूत सुविधाओं की कमी पर लिए स्वप्रेरित प्रसंज्ञान मामले में सुनवाई करते हुए दिए।

- हाई कोर्ट ने केन्द्र व राज्य सरकार से महिला शौचालयों के सुधार पर कार्य योजना माँगी।

सुनवाई के दौरान केन्द्र सरकार की ओर से एएसजी राजदीपक रस्तोगी और राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता माही यादव पेश हुए। दोनों

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

फ्री ट्रेड, फ्री इन्वैस्टमैंट का सबसे बड़ा व प्रबल समर्थक अमेरिका अब इतना कैसे बदल गया?

अमेरिका ने चीन की बड़ी कम्पनियों पर, चीन की सेना से नज़दीकी संबंधों का आरोप लगाकर, अमेरिका में इन कम्पनियों का माल प्रवेश करने पर भारी पाबंदी लगा दी

-अंजन रॉय-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 7 जनवरी। किसी समय युनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका फ्री ट्रेड (मुफ्त व्यापार), फ्री इन्वैस्टमैंट (मुफ्त निवेश) तथा व्यापार एवं उद्योग में किसी भी तरह के सरकारी हस्तक्षेप नहीं होने का सबसे बड़ा हिमायती वही आज अमेरिकी बाज़ार में विदेशी व्यापार व उद्योग को प्रवेश करने से रोकने के लिए सरकारी कंट्रोल का पक्षधर बन गया है।

संयुक्त राज्य अमेरिका ने उन चीनी कंपनियों को चिन्हित किया है जो चीन मिलिटरी से जुड़ी हैं। इस प्रकार उसने सैन्य उत्पादों के लिए लाभकारी व विशाल अमेरिकी बाज़ार में इन चीनी कंपनियों के प्रवेश को प्रतिबंधित कर दिया है।

यू.एस.ए. ने सबसे बड़ी चीनी शिपिंग कंपनी कॉस्को (सी.ओ.एस.सी.ओ.), जो एक मिलिटरी कंपनी है, को चिन्हित किया है, और अमेरिकी बाज़ारों में, शिपिंग व माल ढुलाई के उसके कार्य संचालन को प्रतिबंधित कर दिया है। यह कंपनी चीनी सैन्य हार्डवेयर यूनिट्स के लिए माल और सामान ढोती है।

साथ ही साथ, अमेरिका ने चीन के सबसे बड़ी ऑफशोर तेल उत्पादक, सी.एन.ओ.ओ.सी. पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह एक राज्य समर्थित कंपनी है और चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पी.एल.ए.) के साथ इसके सक्रिय लिंक है। अमेरिका की, रुसी तथा ईरानी तेल कंपनियों और सख्त प्रतिबंध लगाने की योजना है, इन कंपनियों के राजस्व को कम करने के लिए।

एक और अलगाववादी कदम में, यू.एस. सरकार ने जापान की कंपनी निप्पॉन स्टील द्वारा अमेरिका की बीमार स्टील कंपनी, यू.एस. स्टील्स को खरीदने के प्रयास को रोक दिया है। सरकार के इस कदम के जवाब में दोनों कंपनियाँ री-स्ट्रक्चरिंग के लिए पुनः योजना बना रही है।

ये कदम नुकसानदेह हो सकते हैं तथा वैश्विक गैस व तेल की कीमतों को बढ़ा सकते हैं। तेल बाज़ार की रिपोर्टों के अनुसार प्रमुख कच्चे तेलों में पहले ही कड़ी वृद्धि देखी जा रही है। वर्तमान में ब्रैंट क्रूड लगभग 77 डॉलर प्रति बैरल बिक रहा है और सर्दियों की मांग के कारण यह जल्द ही 80 डॉलर तक पहुंच सकता है।

सबसे ज्यादा चौंकाने वाला कदम यह रहा कि अमेरिका ने चीन की सबसे

- पहले अमेरिका का नारा होता था, बिज़नेस व उद्योग पर सरकार का कुछ भी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिये।
- पर, अब बड़ी-बड़ी चीन की कम्पनियों पर, जैसे चीन जल परिवहन की सबसे बड़ी कम्पनी कोस्को, चीन ''ऑफ शोर'' ऑयल प्रोडक्शन की सबसे बड़ी कम्पनी सीनुक तथा चीन की सबसे बड़ी इंटरनैट कम्पनी, टैनसैन्ट पर चीन की सेना से ''लिंक'' होने का आरोप लगाकर, अमेरिका में धंधा करने पर पूरी रोक लगा दी है। यही हाल विश्व में बिजली की कारों के लिये सबसे बड़ी इलैक्ट्रिक बैट्री निर्माता कम्पनी चीन के सी.ए.टी.एल. के साथ भी अमेरिका ने यह ही किया है।
- अब विश्व यह ही देख रहा है कि अमेरिका किन और कम्पनियों पर, सेना से लिंक होने का आरोप लगाकर, अमेरिका में व्यापार करने पर पाबंदी लगायेगा।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

सांसद पप्पू यादव की 12 को बिहार बंद की घोषणा

पटना, 07 जनवरी। बिहार में पूर्णिया के सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) 70 वीं परीक्षा को रद्द कर पुनर्परीक्षा कराने एवं अनियमितताओं की जांच के लिए राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन सौंपा।

- उन्होंने परीक्षा रद्द कर पुनः परीक्षा कराने व अनियमितताओं की जांच के लिये राज्यपाल को ज्ञापन दिया।

यादव ने मंगलवार को यहां बताया कि अब तक हुई सभी परीक्षाओं में पेपर लीक की जांच का आश्वासन राज्यपाल ने दिया है। उन्होंने राज्यपाल को बताया कि बीपीएससी की 70वीं पीटी परीक्षा

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

दिल्ली विधानसभा चुनाव 5 फरवरी को, मतगणना 8 फरवरी को

चुनाव आयोग ने दिल्ली विधानसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की

-डॉ. सतीश मिश्रा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 7 जनवरी। जैसी आशा थी, भारतीय चुनाव आयोग ने आज दिल्ली विधानसभा चुनावों की घोषणा कर दी। मतदान एक ही चरण में, 5 फरवरी को होगा तथा परिणामों की घोषणा तीन दिन बाद, 8 फरवरी को की जायेगी।

इन चुनावों में तीनों पार्टियों- आम आदमी पार्टी (आप), इसे मुख्य चुनौती देने वाली भाजपा तथा कांग्रेस का बहुत कुछ दाँव पर लगा हुआ है। राष्ट्रीय राजधानी में कभी बहुत प्रभावी रही कांग्रेस और भाजपा एक दशक पुरानी आप को हराने में कोई कसर नहीं छोड़ रही हैं। आप ने इन दोनों पार्टियों को दिल्ली में दीन-हीन स्थिति में पहुँचा दिया है।

जहाँ भाजपा जनता की नज़रों में आप की जबरदस्त छवि को नष्ट करने के लिये उचित-अनुचित सभी तरह के तरीके अपना रही है, वहीं कांग्रेस, जिसके पास संसाधनों का नितान्त अभाव है, तीसरी ताकत के रूप में दृढ़तापूर्वक संघर्ष कर रही है।

भाजपा के लिये यह लड़ाई इसलिये और भी प्रतिष्ठा की हो गई है, क्योंकि गत वर्ष के लोकसभा चुनावों में उसे अपेक्षित सफलता भले ही न मिली हो, लेकिन कुछ माह पूर्व हुये हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में उसने चौंका देने वाली वापसी की है। इस चुनाव में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तथा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की ब्रान्ड वैल्यू दाँव पर लगी हुई है।

जहाँ आप के लिये यह चुनाव अब तक का सबसे मुश्किल चुनाव है, वहीं भाजपा लगभग ढ़ाई दशक बाद, सत्ता में लौटने के लिये एड़ी-चोटी का जोर लगा रही है। दूसरी तरफ, कांग्रेस दोनों का सामना करने के लिये बाध्य हैं, हालाँकि उसे मालूम है कि उसे जो भी मिलेगा, वह उसे शिरोधार्य होगा क्योंकि उसके पास खोने के लिये कुछ भी नहीं है।

एक भ्रष्टाचार-विरोधी आंदोलन की कोख से जन्मी आप 2013 में, अपने पहले चुनाव में आँधी-तूफान की तरह आई और 29.49 प्रतिशत वोट शेयर के साथ, दिल्ली की 70 में से 28 सीटें जीत लीं। दो साल बाद, 2015 में, इसने अपने विरोधियों को धूल चटा दी तथा 70 में से 67 सीटें जीतीं तथा भाजपा को केवल 3 सीटें और कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली। 2015 में इसका वोट शेयर 54.35 प्रतिशत रहा। आप ने अपना यह असाधारण प्रदर्शन 2020 में भी दोहराया। इसकी सीटों में मामूली सी कमी आई तथा इसे 62 सीटें मिलीं तथा वोट शेयर 53.70 प्रतिशत रहा।

लेकिन, जिस पार्टी ने कभी अपने आप को परिवर्तन की प्रतिनिधि के रूप में प्रोजैक्ट किया था, वही पार्टी भ्रष्टाचार के आरोपों से घिर चुकी है। स्वयं केजरीवाल ने करीब 6 महीने जेल में गुजारे हैं। दिल्ली के कथित आबकारी नीति घोटाले में उनकी भूमिका को लेकर पहले उन्हें ई.डी. ने गिरफ्तार किया था तथा उसके बाद सी.बी.आई. ने। उन्हें गत वर्ष सितम्बर में जमानत मिली थीं

केजरीवाल के मुख्य सहयोगी तथा दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी आबकारी नीति केस में 17 महीने से ज्यादा समय तक जेल में रहे थे। एक अन्य पूर्व मंत्री सत्येन्द्र जैन तथा राज्यसभा सांसद संजय सिंह भी गिरफ्तार हुये थे तथा इस समय वे जमानत पर हैं।

2015 से दिल्ली के राजनैतिक परिदृश्य पर छाई रही तथा 2022 में एक दूसरे राज्य, पंजाब में जीत का डंका बजाने वाली आप, पिछले कुछ दशकों में भारत की सर्वाधिक सफल पोलिटिकल स्टार्टअप रही है। इसकी सफलता के पीछे केजरीवाल का वैलफेयर मॉडल था, जिसमें मोहल्ला क्लीनिक, सरकारी स्कूलों में सुधार, बिजली तथा पानी में दी गईं सब्सिडी शामिल थे। लेकिन इसके साथ ही सत्ता-विरोध, बुरी तरह खराब हो चुकी इसकी छवि तथा इसकी चमक-दमक का फीका पड़ना- जैसे कारण इसके लिये संकट बन रहे हैं।

भाजपा, जिसे उच्च मध्यम वर्ग, पंजाबी समुदाय तथा व्यापारी वर्ग का समर्थन हासिल है, के वोट बैंक में इस प्रकार की कोई कमी दिखाई नहीं दे रही है।

भाजपा का पूरा फोकस भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आप को निशाना बनाने तथा मुख्यमंत्री निवास के कायाकल्प में की गई फिजूलखर्ची को लेकर केजरीवाल पर व्यक्तिगत हमले करने पर है। आप को पहली बार भ्रष्टाचार के मुद्दे पर विरोध का सामना करना पड़ रहा है। केजरीवाल ने कभी स्वयं को एक ऐसे ''शिक्षित'' बाहरी

- दिल्ली विधानसभा का चुनाव त्रिकोणात्मक हो रहा है, आप, भाजपा और कांग्रेस एक-दूसरे को टक्कर देंगे। आम आदमी पार्टी के लिए यह अब तक सबसे कठिन चुनाव है, वहीं भाजपा भी 25 साल बाद सत्ता में वापसी की उम्मीद कर रही है। साथ ही कांग्रेस भी बेहद आशान्वित है।
- भाजपा ने बेहद उग्र प्रचार अभियान छेड़ रखा है। उसका निशाना केजरीवाल हैं। यहाँ प्रधानमंत्री ने खुद मोर्चा संभाला है।
- इस बार कांग्रेस भी दिल्ली को लेकर बेहद आशान्वित है। वर्ष 1998 के विधानसभा चुनाव में शानदार जीत के साथ कांग्रेस लगातार 15 साल सत्ता में रही, जिसे 2013 में आप ने सत्ता से बेदखल किया।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)